



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 423) पटना, मंगलवार, 7 अप्रील 2015

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

1 अप्रील 2015

सं0 10/व 3-62/91अंश-291—डॉ० सैयद मोहिबुल हसन, को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर अधिसूचना संख्या-87 दिनांक 07.02.2015 द्वारा नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति हेतु दिनांक 24.12.2014 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रस्ताव दिया गया जिसका अनुमोदन तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक 06.02.2015 को किया गया। उक्त प्रस्ताव में डॉ० हसन अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं अथवा नहीं इसकी विवेचना नहीं किया गया। संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि डॉ० हसन ने अपना बायोडाटा माननीय मंत्री को 18.12.2014 को उपलब्ध कराया था एवं उसके उपरान्त माननीय मंत्री ने विभाग के प्रधान सचिव को उन्हें अध्यक्ष पद पर मनोनयन हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया था। समर्पित बायोडाटा में उनकी शैक्षणिक परिलब्धियों के संबंध में यह अंकित है कि “बी० ए० आनर्स एम० ए० (राजनीति विज्ञान), एम० ए० (इतिहास), एल० एल० बी०, पी-एच० डी० (Indias Stand on Nuclear Disarmament) हैं”।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत मदरसा बोर्ड गठित हैं। उक्त अधिनियम की धारा-10 (2) में यह प्रावधान है कि “अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु कोई व्यक्ति तबतक योग्य नहीं समझा जाएगा जबतक वह केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव न रखता हो अथवा वह स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थान में न्यूनतम 10 वर्षों का शिक्षण अथवा शोध का अनुभव न रखता हो अथवा अरबी, फारसी, इस्लामिक अध्ययन में ख्याति प्राप्त विद्वान न हो और मदरसा शिक्षा में अभिरुचि न रखता हो”। अधिनियम में उल्लेखित उपरोक्त प्रावधान को ध्यानस्त उनके अर्हता एवं नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया यह दृष्टव्य हुआ कि वह अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करते हैं। तदोपरान्त, अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता के संबंध में उनसे दो दिनों में स्पष्टीकरण की माँग की गई। डॉ० हसन ने उत्तर हेतु सात दिनों के समय की माँग की जिसे स्वीकार किया गया। दिनांक 18.03.2015 को उन्होंने अपना उत्तर समर्पित किया जो विभाग को 19.03.2015 को प्राप्त हुआ। अपने उत्तर में उन्होंने यह कहा है कि अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में शोध का अनुभव भी सम्मिलित है जो उन्हें उपलब्ध हैं और इस आधार पर उन्होंने अपनी नियुक्ति को वैध माना।

उनके स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने अपने शोध के अनुभव के समर्थन में और न तो अपनी नियुक्ति के समय और न ही अपने स्पष्टीकरण के साथ कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया है।

उन्होंने मात्र शोध के अनुभव की चर्चा की हैं। अधिनियम में यह स्पष्ट है कि नियुक्ति हेतु स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान में 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव अथवा 10 वर्षों के शोध का समतुल्य अनुभव होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त उनकी नियुक्ति में इस तथ्य की विवेचना भी नहीं हुआ कि वह पद हेतु अर्हति हैं अथवा नहीं।

उनका उत्तर पूर्णतः असंतोषप्रद है इस कारण बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति शून्य (void ab initio) हैं। अतएव तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाता है।

यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि उनके अध्यक्ष पद के अल्प अवधि में ही उनके विरुद्ध कतिपय प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप प्राप्त हुए हैं जिसकी जाँच हेतु विभाग में एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यद्यपि की आरोपो की जाँच का उनकी नियुक्ति रद्द किए जाने के आदेश से कोई संबंध नहीं है तथापि आरोपों के फलाफल के अनुरूप उनके विरुद्ध अलग से विधिसम्मत कार्रवाई किया जा सकेगा।

डॉ० हसन को अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप एक महीने का वेतन देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव, मा0 शिक्षा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 423-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>